(c) The National Programmes for Malaria, AIDS, T.B. and Cancer are being implemented according to their approved pattern of assistance.

Malaria:- The budget for Malaria has been increased and external aid has been availed of to be able to improve vector control measures, build up awareness, promote personal protection and involve the community.

Tuberculosis:- A Tuberculosis control project envisaging Directly Observed Short Course Chemotherapy (DOTS) covering a population of 271 million in 102 districts has been launched in March, 1997. The project is assisted by the World Bank.Government has also approved the change in the funding policies for the Tuberculosis. Programme and for the first time the programme will fund 100% supply of drugs to the States. This is a major step which will help maintain uniform supply of Tuberculosis drugs in the endemic areas of the country.

AIDS:- For surveillance of HIV infection, HIV testing facilities exist in 62 Surveillance centres all over the country. 55 Sentinel sites are attached to these centres to monitor the trend of HIV infection among various high risk groups of population. The establishment of 154 Zonal Blood Testing Centres, modernization of 815 Blood Banks, establishment of 40 Blood Component Separation Facilities and promotion of voluntary blood donation have been given a thrust. In addition 504 STD Clinics have been strengthened and training of doctor and laboratory technicians on a wide scale has also been undertaken.

Cancer:- The following important initiatives are being continued to give an impetus to cancer control activities:-

1. Augmentation of Regional Cancer Centres.

2. Development of Oncology Wings in the medical colleges.

3. Installation of Cobalt-60 teletherapy equipment.

Implementation of District Cancer Control Projects.

Cholera and Dengue are seasonal diseases and the control of the same is a public helath responsibility discharged by the State Governemnts. The Central Government gives them guidelines on the control and management of diseases and alerts them about important measures that need to be taken on a location specific basis.

विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाना

*224. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान किए जाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुवैत, बंगलादेश इत्यादि जैसे देशों से भारतीय मूल के लोगों के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की तरह व्यवहार किए जाने की शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार इस संबंध में संबंधित सरकारों के साथ क्या कदम उठा रही है और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) क्या सरकार भारतीय मूल के लोगों के हितों का संरक्षण करने के लिए उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान करने का विचार रखती है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा): (क) से (ङ) विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की संख्या का देश-वार अद्यतन ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय मूल के व्यक्ति जब एक बार दूसरे देश की राष्ट्रीयता ग्रहण कर लेते हैं और उसके प्रति निष्ठा की शपथ ले लेते हैं तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य उस देश का हो जाता है जहां की उन्होंने स्वेच्छा से राष्ट्रीयता ग्रहण की होती है। तदनुसार, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य भारत सरकार का नहीं रह जाता। वास्तव में, ऐसे व्यक्तियों के कल्याण में अत्यधिक रुचि को दूसरे प्रभुतासम्पन्न राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप समझा जा सकता है। तथापि, भारत सरकार भारतीय मूल के लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए मेजबान सरकारों और भारतीय मूल के लोगों के संगठनों के साथ सावधानी के साथ सम्पर्क बनाए रखती है ताकि उनके और भारत के बीच सांस्कृतिक सम्पर्कों को निरन्तरता प्रदान की जा सके।

भारतीय मूल के लोगों के विरुद्ध भेदभाव की जो भी खबरें हैं भारत सरकार ऐसे आरोपों से सावधानीपूर्वक निपटती है और आवश्यक होने पर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुरूप सम्बद्ध सरकार के साथ उपयुक्त स्तर पर उठाती है।

भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

Funds for different Programmes in Municipalities in Andhra Pradesh

*225. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether any Central funds were made available to Andhra Pradesh Government in 1995-96 and 1996-97 for various programmes in Municipalities;

(b) if so, the quantum of such funds

(c) whether Government monitor and react to complaints of misuse or diversion of funds in their end-use;

(d) whether Government have received any representations from Municipal Councillors of ELURU in Andhra Pradesh on such improper diversion; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OR URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) Yes, Sir.

(b) The funds released during 1995-96 and 1996-97 were Rs.3600.42 and Rs.3228.13 lakhs respectively.

(c) Under the guidelines for various Centrally Sponsored Schemes, State Governments are responsible for their implementation and monitoring. As and when issues come to the notice of Government of India, the same are referred to State Governments for appropriate action. However, no report regarding complaints of misuse/diversion of funds have been received so far.

(d) No, Sir.

(e) Question does not arise.

आग लगने की संभावना वाले केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के भवन

*227. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नई दिल्ली/दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय जिन भवनों में स्थित हैं, वे अग्निशमन कार्यालय द्वारा असुरक्षित घोषित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन भवनों को सुरक्षित बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई अनिष्टकारी घटना न हो?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेस्वरलू): (क) दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा नई दिल्ली/दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित केन्द्र सरकार के कार्यालयों वाली किसी इमारत को असुरक्षित घोषित नहीं किया गया है। किन्तु उन्होंने उनमें कुछ कमियां अवश्य बताई हैं।